हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 20 | लखनऊ शनिवार 17 मई 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

पीएम मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति और सेना की ताकत का प्रतीक, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले अमित शाह

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नए मल्टी–एजेंसी सेंटर का उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति, एजेंसियों की सटीक खुफिया जानकारी और सेनाओं की अचूक ताकत का प्रतीक है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जोर दिया। शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और भारतीय सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं की सटीक और ताकतवर कार्रवाई का बेहतरीन उदाहरण है।

नए मल्टी–एजेंसी सेंटर के उद्घाटन पर बोले शाह

शाह ने यह बात दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक नए मल्टी–एजेंसी सेंटर (एमएसी) का उद्घाटन करते हुए कही।

एमएसी देश की विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान को तेज और प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है। बता दें कि मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी, ताकि सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समय रहते जानकारी साझा की जा सके और आतंकी खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

मामले में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बताया कि यह नया सेंटर खुफिया तंत्र को और अधिक कुशल बनाकर आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में मदद करेगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों की तैयारी को जाता है।

आतंक से निपटने के लिए होगा अहम

अजमेर : इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग के बाद मचा हड़कंप, विधायक अनीता भदेल ने एक्सईएन को फटकारा

अजमेर। शहर के आशागंज क्षेत्र में सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम–गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा–तफरी मच गई। इस हादसे में 200 से ज्यादा कूलर, एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। आग का कारण विद्युत वायर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचीं अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए मौके पर मौजूद एक्सईएन आकांक्षा को जमकर फटकार लगाई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आग की चपेट में आई तीन मंजिला बिल्डिंग घटना सुबह उस समय हुई जब संत कंवरराम स्कूल के पास स्थित तीन मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। तेज गर्मी और हवा के चलते आग तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। पास ही स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय की दीवार तक आग पहुंच गई, जिससे बैंक का सायरन बजने लगा। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बैंक और आस–पास की इमारतों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन

बिल्डिंग में दरारें आ गईं। सावधानी के तौर पर आसपास की दुकानें और बिल्डिंग खाली करवाई गईं। विधायक का फूटा गुस्सा रू शब जल जाता है तब तुम आते हो?

घटनास्थल पर पहुंचीं विधायक अनीता भदेल का गुस्सा नगर निगम अधिकारियों पर फूट पड़ा। उन्होंने नगर निगम की एक्सईएन आकांक्षा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा जब जल जाता है, तब तू थप्पड़ मारने आती है? इतनी सारी बिल्डिंगों में फायर एनओसी है या नहीं, तुझे मालूम भी है? जब आकांक्षा ने जवाब दिया कि उन्हें हाल ही में अजमेर दक्षिण का चार्ज मिला है और नगर निगम आयुक्त ने कार्रवाई की छूट दी है, तो भदेल ने कहारू तुम लोगों को कार्रवाई हमेशा नुकसान के बाद ही याद आती है।

आज से पहले तुम्हें ये बिल्डिंग नजर नहीं आई क्या? शधिक्कार है नगर निगम के ऐसे अधिकारियों पर विधायक भदेल ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि शहर में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं होता। मगर नगर निगम तब जागता है जब लाखों का नुकसान हो चुका होता है। यह मानवता नहीं है, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर।

व्यापारियों को दी सावधानी बरतने की सलाह विधायक भदेल ने व्यापारियों से अपील की कि वे गर्मी के मौसम में विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, कूलर, एसी या परचूनी दुकानें चलाने वाले व्यापारी समय रहते वायरिंग और इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस करवा लें। प्रतिष्ठान छोड़ने से पहले सभी कनेक्शन हटाकर जाएं ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट न हो। प्रशासन ने संभाला मोर्चा, जांच जारी घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग मालिक गुरचरण सिंह से पूछताछ की गई है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शोरूम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे या नहीं, और क्या फायर एनओसी और बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, इसकी भी जांच की जा रही है। राजनीतिक रंग भी पकड़ रहा मामला घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने विधायक के रुख का समर्थन किया है तो कुछ ने इसे लोकल अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाला कदम बताया है। वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस घटना को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नुकसान का आंकलन और अगली कार्रवाई शोरूम संचालक के अनुसार आग में करीब 25–30 लाख रुपये का माल जलकर खाक हो गया है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन कराया जा रहा है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।

यूपी सरकार ने गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने के लिए खोला खजाना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है। योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि उठाई, धराई और अंतर्राज्यीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री के सुचारू वितरण के लिए स्वीकृत की गई है, जो खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यक्षमता को नई गति देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत योगी सरकार एक–एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है और इसके लिए अभियान चलाकर पात्रता की पहचान की जा रही है।

उपर्युक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ली गई है, जिसके अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50–50 रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सक्षम और व्यापक बनाना है, ताकि लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन, भंडारण, सामग्री की लदान–उतरान, उचित दर दुकानों

तक राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था शामिल है। यह राशि खाद्य भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर खाद्यान्न वितरण में बाधा न आए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि पूर्व में दी गई वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकतानुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला नहीं हो, इसके लिए ई–केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई–केवाईसी कराने की सुविधा मिल रही है। राशन वितरण में ई–पॉस मशीनों के उपयोग ने पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन मशीनों के जरिए अन्न का वितरण सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यह तकनीकी नवाचार न केवल समय पर राशन उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। पात्र कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल मिलाकर 5 किलो) फ्री में दिया जा रहा है। वहीं, अंत्योदय कार्ड धारक को एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) दिए जा रहे हैं।

पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद, पीओके पर होगी, श्रीनगर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

श्रीनगर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर स्थित बादामी बाग कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आज आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं, जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में हताहत हुए सभी निर्दोष नागरिकों और श्ऑपरेशन सिंदूरश्च के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं, हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इस विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आकर आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में श्ऑपरेशन सिंदूरश्च के दौरान आपने जो कुछ किया, उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो भारत का नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ–साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आपका आभार प्रकट करने आया हूं। उन्होंने कहा, मैं आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं, जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को ध्वस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ–साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आया हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता लेकर मैं आपके बीच आया हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं।

जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को ध्वस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ–साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आया हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता लेकर मैं आपके बीच आया हूं। एक संदेश यह है, कि श्हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि श्ऑपरेशन सिंदूरश्च सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है। एक ऐसी प्रतिबद्धता, जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते, जब वक्त आता है, तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं। यह ऑपरेशन उस एक–एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वो घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर, हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही लौटेंगे। उन्होंने कहा, श्ऑपरेशन सिंदूरश्च आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35–40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो–टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमीं पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक श्एक्ट ऑफ वॉरश्च माना जाएगा। दोनों देशों में जो समझ अभी बनी है, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी।

रक्षा मंत्री ने आतंकियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि श्ऑपरेशन सिंदूरश्च की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ–साफ बता दिया है कि वो कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है कि हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गईं हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को आईएईए यानी (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) की निगरानी में लिया जाना चाहिए।

भीख मांगना पाकिस्तान का काम, सिंधु जल संधि पर पीएम मोदी नहीं करेंगे रहम : सीपी सिंह

रांची। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने गुरुवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की ओर से भारत से लगाई जा रही गुहार पर कहा कि पाकिस्तान का काम भीख मांगना है और वह फिर घुटने के बल भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन, पीएम मोदी के नेतृत्व में यह भारत उस पर रहम नहीं करेगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि पहलगाम में आंतकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। जिसमें सिंधु जल संधि भी शामिल है, जो फिलहाल निलंबित है। एयरबेस, सोशल मीडिया हैंडल सहित कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बेहद ही बेशर्म और बुजदिल देश है। भारत से बार–बार झटके खाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलता। कुछ होते हैं जो मार खाने के बाद सुधरते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वर्तमान में अभी भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार खानी पड़ी। पूर्व में भी उसे कई बार मार पड़ी है। लेकिन, वह मार खाने के बाद हर बार की तरह घुटनों के बल भारत से भीख मांगने लगता है। लेकिन अब गिड़गिड़ाने से क्या होगा। भारत ने जिस प्रकार पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया है। पाकिस्तानी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे अपनी आवाम के सामने इज्जत बचाए। इसीलिए, आवाम के सामने झूठे दावे पेश करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात सिंधु जल संधि की है तो यह स्थगित ही रहनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी पाकिस्तान पर रहम नहीं करेंगे बल्कि कड़ाई करेंगे।

सीएम की हरी झंडी, बंगाल में होगा 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश

कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन (बीजीबीएस) के मंच पर जो नींव गाड़ी थी, वह अब साकार होने की ओर अग्रसर है।कारण विभिन्न व्यापारिक समूहों द्वारा बंगाल की ममता सरकार को विशिष्ट निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। अब ममता बनर्जी की कैबिनेट ने औद्योगीकरण के लिए भूमि व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया। 2021 में तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, ममता ने घोषणा की कि इस बार उनका मुख्य लक्ष्य औद्योगीकरण है। बुधवार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ष्हमारा लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन है। आज कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि राज्य में निवेश को लेकर औद्योगिक समूहों की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर आज निर्णय लिए गए। राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधीन पुरुलिया, दुर्गापुर और पानागढ़ सहित 10 स्थानों पर कुल 2,515 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन सभी जगहों पर 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार 70,000 होगा। ममता ने कहा कि प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से अधिकांश इस्पात उद्योग में हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 15 औद्योगिक तालुकों में 43 कंपनियों को लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। कई महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि, टॉलीवुड के कई लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हर जिले में सिनेमा हॉल बनाए जाएं। प्रस्ताव मिलने पर ममता ने घोषणा की कि पीपीपी मॉडल का उपयोग करके हर जिले में शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे। उस मॉल में एक सिनेमा हॉल भी होगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 11 जिलों में शॉपिंग मॉल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। इस सूची में पुरुलिया, दार्जिलिंग, हावड़ा, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा जैसे जिले शामिल हैं। ममता ने कहा कि शेष 12 भी प्रक्रिया में हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस शॉपिंग मॉल की कम से कम दो मंजिलें स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल के लिए आरक्षित रहेंगी। बहरहाल मुख्यमंत्री अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा करने वाली हैं। वह सोमवार को सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल के व्यापारिक समुदाय से मुलाकात करेंगे। ममता ने निवेश में प्रक्रियागत जटिलताओं को दूर करने के लिए पिछले फरवरी में विश्व बंगाल व्यापार शिखर सम्मेलन में तालमेल समिति के गठन की घोषणा की थी। वह इस मुद्दे पर उत्तर बंगाल के व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार को उनका जलपाईगुड़ी के ओडलाबाड़ी में सरकारी सेवा वितरण कार्यक्रम है। ममता बुधवार को उत्तरकन्या (उत्तर बंगाल में राज्य सरकार सचिवालय) में प्रशासनिक समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में उत्तर बंगाल के सभी जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे।

सम्पादकीय

नहीं मानेगा पाक

ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से भारत के निपटने के तरीके में बड़े बदलाव को स्थापित कर दिया। यह केवल सैन्य अभियान–भर नहीं था, बल्कि दुनिया को साफ तौर पर संदेश था कि भारत सीमा पार हमलों पर अब चुप नहीं बैठेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोगों के मारे जाने के ठीक दो हफ्ते बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और आक्रोश और गुस्से में भरे लोग दुख में एकजुट हो गये थे। भारत सरकार ने अब बहुत हो गया की सोच के साथ तुरंत और दृढ़ता से आतंकी हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की। विचारपूर्वक की गई जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा और हिज़बुल मुजाहिदीन के नौ आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये आतंकी शिविर मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप और अब्बास कैंप, भीमबेर में बरनाला कैंप, सियालकोट में सरजल कैंप और महमूना जोया कैंप, मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप और बहावलपुर में मरकज सुभानल्लाह थे। भारत के इस अभियान का टॉम कूपर, जॉन स्पेंसर और जेनिफर ज़ेंग जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने विस्तृत मूल्यांकन किया है, जिसमें भारत की सफलता के रणनीतिक और सामरिक तत्वों को रेखांकित किया गया है। रणनीतिक सटीकता और वायु युद्ध श्रेष्ठता ऑस्ट्रियाई सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने भारत के वायु सेना अभियान को जीत की स्पष्ट वजह बताया है। कूपर ने कहा है कि पाकिस्तान की विश्वसनीय कार्रवाई अक्षमता से भारत की रणनीतिक प्रभावशीलता परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा, इस मामले मेंरू भारत की स्पष्ट जीत हुई है और कोई हैरत नहीं कि पाकिस्तान ने युद्धविराम के लिए क्यों आवाज़ लगानी शुरू की। कूपर ने अपने तर्क के समर्थन में पाकिस्तान की प्रतिरोधी रणनीतिक विफलता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और परमाणु हमले की धमकी देने की रणनीति विफल रही, क्योंकि भारत ने जोरदार जवाबी हमला किया और पाकिस्तानी कदम के जवाब में हमला और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई इसलिए थमी कि पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाने के बाद युद्ध विराम का आग्रह करना शुरू कर दिया। कूपर ने विचार व्यक्त किया कि पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला संभवतरू उसके गोला–बारूद के अपर्याप्त भंडार और नष्ट होते यूएवी के कारण हुआ। नये युद्ध सिद्धांत और रणनीतिक स्वतंत्रता मॉडर्न वारफेयर इंस्टीट्यूट–अर्बन वॉरफेयर स्टडीज़ के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने रणनीतिक संयम और दृढ़तापूर्ण भारतीय रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की चेतावनी भरी लाल रेखाओं को फिर से परिभाषित कर दिया कि पाकिस्तान की भूमि से उस पर किया जाने वाला कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। स्पेंसर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत ने प्रचंड जवाबी हमला किया लेकिन इसे युद्ध में बदलने से पहले ही रोक दिया। यह उल्लेखनीय प्रतिरोधक प्रदर्शन है, जो नपा–तुला, नियंत्रित और विश्वसनीय रहा। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बड़ी जीत बताया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ 'चार दिनों की विचारपूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लिया। स्पेंसर इसे निर्णायक शक्ति और उसे स्पष्ट तौर पर लागू किये जाने के प्रयोग के रूप में देखते हैं, न कि सिर्फ 'प्रतीकात्मक बल के रूप में।

जातीय जनगणना पर कांग्रेस का धोखा: सामाजिक न्याय या सियासी रणनीति?

लेखक समाजसेवी वसीम राईन

जातीय जनगणना को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ओबीसी वर्ग के अधिकारों की बात जब–जब उठती है, तब–तब कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठने लगते हैं। एक ओर जहां ओबीसी के लाल नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कदम बढ़ाए हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी सरकार के रहते जातीय जनगणना पर प्रतिबंध लगाने वाली कांग्रेस पार्टी अब भी स्पष्ट रुख अपनाने से बचती दिख रही है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल के दौरान जातीय जनगणना को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाले रखा। वजह साफ थी, अगर जातियों के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाते, तो श्बांटो और राज करोश की उसकी राजनीति का चेहरा बेनकाब हो जाता। जातिगत समीकरण को धुंधला रखकर कांग्रेस ने वर्षों तक सामाजिक वर्गों को केवल एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दों को केवल चुनावी मंचों पर भुनाया है, जबकि उसे कानूनी और संवैधानिक रूप देने की दिशा में कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि जब तक जातीय आंकड़े आधिकारिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक सामाजिक न्याय केवल एक नारा ही बना रहेगा। राहुल गांधी पर भी कई सवाल खड़े करती है। जब देश भर में सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है और वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तब विपक्ष के एक बड़े नेता का जाति जनगणना बिल लाकर एक्ट बनवाने कोई दिलचस्पी नहीं हैं उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस वाकई में सामाजिक समानता की पक्षधर है या फिर वह सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझी हुई है? जातीय जनगणना को सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा न बनाकर संसद में सेंसस अमेंडमेंट बिल लाया जाए, ताकि इसे सेंसस अमेंडमेंट एक्ट के रूप में कानूनी दर्जा मिल सके। इससे सामाजिक भागीदारी के साथ–साथ संसाधनों के वितरण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें इस वर्ग की पीड़ा व स्थिति की गहराई से समझ है। यही कारण है कि उन्होंने वह करके दिखाया, जो दशकों तक कांग्रेस नहीं कर सकी। यह कदम न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि देश की सामाजिक संरचना में संतुलन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, बल्कि सवाल यह है कि कौन ईमानदारी से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात कर रहा है। कांग्रेस की खामोशी उसकी पुरानी सोच को उजागर करती है, एक ऐसी सोच, जो हाशिए पर खड़े समाज को बराबरी का हकदार नहीं, बल्कि केवल वोट बैंक मानती है। जातीय जनगणना कोई आंकड़ों का खेल नहीं, यह सामाजिक बदलाव का आधार बन सकती है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता के साथ इसे लागू किया जाए। समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करें, क्योंकि अब देश सिर्फ वादे नहीं, बदलाव चाहता है।

विपक्षी गठबंधन की चिंता में जाति जनगणना फैसला

अजीत द्विवेदी

यह लाख टके का सवाल है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करा लेगी उसके बाद क्या होगा? कुछ भोले भाले राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जाति जनगणना बहुत अच्छी है लेकिन उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके आंकड़ों का इस्तेमाल वंचित समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है। लेकिन भारत में कभी भी आदर्श स्थिति में कोई काम नहीं होता है। यहां सारा काम राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से होता है। इसलिए यह तय मानें कि जातियों की गिनती से जो भी आंकड़ा आएगा उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा। यह भी तय मानें कि सामाजिक–आर्थिक गणना में किसी को आर्थिक स्थिति के आंकड़ों से कोई मतलब नहीं होगा। किस जातीय समूह की आर्थिक स्थिति क्या है यह जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। बिहार की जाति गणना इसकी मिसाल है। उसके मुताबिक बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी मासिक आय छह हजार रुपए से कम है। सोचें, एक परिवार में अगर पांच आदमी है और परिवार महीने में छह हजार रुपए कमा रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करीब पांच करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी मासिक आमदनी छह सौ रुपए है। लेकिन इस आंकड़े से किसी को कोई सरोकार नहीं है। सबका सरोकार इस बात से है कि बिहार में पिछड़े और अतिपिछड़े 63 फीसदी हैं, दलित करीब 20 फीसदी हैं और सवर्ण साढ़े 15 फीसदी हैं। तभी जाति जनगणना से जो भी आंकड़े आएंगे उसमें अलग अलग जातीय समूहों की आर्थिक स्थिति से किसी को कोई मतलब नहीं होगा। सबको जाति के आंकड़ों से मतलब होगा। किस जाति की कितनी संख्या है। इससे कुछ जातियों का वर्चस्व हो सकता है कि कम हो तो कुछ नई

जातियों का वर्चस्व स्थापित हो। तभी सभी जातीय समूहों की ओर से सोशल मीडिया में अपील की जा रही है कि सब अपनी मूल जाति लिखें। कोई भी व्यक्ति अपनी उप जाति या गोत्र या उपनाम आदि को जाति के तौर पर दर्ज नहीं करे। ध्यान रहे पिछली बार सरकार ने जातियों की सूची नहीं बनाई थी इसलिए लाखों जातियां दर्ज हो गईं। लोगों ने जाति की जगह उपजाति, अपना मूल, गोत्र, गांव का नाम, उपनाम आदि दर्ज कराया। इस बार कहा जा रहा है कि सरकार अंग्रेजों के जमाने में दर्ज करीब चार हजार जातियों की सूची बनाएगी और लोगों से उसी में से जाति चुनने को कहा जाएगा। हालांकि अभी जाति जनगणना की कोई टाइमलाइन तय नहीं है फिर भी जातियों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है और पहला चुनाव बिहार विधानसभा का है। यह स्पष्ट है कि फैसला अचानक नहीं हुआ है। भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद से इस पर विचार कर रही थी। उसको लग रहा था कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और जाति जनगणना कराओ का इंडियाय ब्लॉक का अभियान कामयाब रहा, तभी भाजपा की सीटें कम हुईं। इसलिए भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव हारने की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। विपक्ष को अंदाजा नहीं था कि सरकार यह फैसला करेगी।

आखिर संसद में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा हुआ है कि सरकार ने नीतिगत तौर पर जाति गणना नहीं कराने का फैसला किया है। यह बात 2021 में सरकार ने कही थी। लेकिन 2024 के नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। अब पक्ष और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ चल रही है। भले भाजपा के नेता कुछ भी कहें लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन की चिंता में यह फैसला किया है। तभी सवाल है कि इसके आगे क्या? विपक्ष की चिंता में या विपक्ष का एजेंडा छीन लेने की रणनीति के तौर पर सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके बाद सरकार क्या करेगी? विपक्ष को जीत का स्वाद लग गया है। इसलिए वह जाति जनगणना के बाद का एजेंडा तय कर रहा है। क्या विपक्ष की चिंता में सरकार उसके बाकी एजेंडे को भी स्वीकार करेगी? विपक्ष का एजेंडा है आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को समाप्त करने का। उसका एजेंडा है निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करने का।

नया एजेंडा है न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का। नया एजेंडा है निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण लागू करने का। नया एजेंडा है सरकारी ठेके और खरीद में आरक्षण देने का और नया एजेंडा है लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए तैयार होगी? राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के समय से नारा लगा रहे हैं कि श्जितनी आबादी उतना हक्य। यह इस समाजवादी नारे की तरह है कि श्पिछड़ा पावे सौ में साठ्य। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने भी नारा दिया था, श्जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारीय। सो, कह सकते हैं कि राहुल गांधी कोई नया नारा नहीं दे रहे हैं लेकिन चूंकि वे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं इसलिए उनके नारा देने का असर ज्यादा है। अगर वे आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को कूड़े के ढेर में फेंकने की बात कर रहे हैं तो सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती है। सबको पता है कि यह सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कूड़े में फेंकने में राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं और यह हकीकत भी है कि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसी तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या सीमित है और वहां गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है। नौकरी निजी सेक्टर में है और शिक्षा भी निजी संस्थानों में ही है। इसलिए विपक्षी पार्टियां निजी नौकरियों और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रही हैं। सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले से पहले कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपना अधिवेशन किया था, जिसमें आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने एजेंडा जारी किया, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका और विधायिका में आरक्षण की मांग की। अगर सरकार एक बार विपक्ष के आगे झुकी है और उसके दबाव में जाति गणना करा रही है तो फिर जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने, निजी नौकरी व निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने, ठेके या सरकारी खरीद में आरक्षण देने और न्यायपालिका व विधायिका में आरक्षण लागू करने की मांग से कैसे इनकार करेगी? वैसे इससे पहले सरकार किसानों के सामने भी झुकी थी और उसका आंदोलन खत्म कराने के लिए तीनों विवादित कृषि कानून वापस लिए थे। लेकिन उस समय किया गया कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है और अब किसान आंदोलन इतने हिस्से में बंट गया है कि एक साल से ज्यादा चले उनके आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि किसान आंदोलन और आरक्षण का मामला अलग अलग हैं। लेकिन यह सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना के आंकड़े जातियों के अंदर ऐसा विभाजन बनवा देंगे कि सरकार को विपक्ष के एजेंडे की चिंता करने की जरुरत नहीं रह जाएगी? हो सकता है कि जातियों के आंकड़े से कुछ जातियों का वर्चस्व टूटे, कुछ नई जातियां ताकतवर होकर उभरें, आरक्षण के लाभ से वंचित रही जातियों की हकीकत सामने आए और सरकार आरक्षण का वर्गीकरण करके उन जातियों को सशक्त बनाने का प्रयास करे, जिससे नए सामाजिक व राजनीतिक समीकरण बनें। यह भी हो सकती है कि कुछ पिछड़ी जातियां सामान्य वर्ग की जातियों से आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त निकलें। उनका क्या किया जाएगा?

आर्थिक आंकड़ों के आधार पर क्रीमी लेयर की नई सीमा तय हो सकती है। कहने का मतलब है कि यथास्थिति टूटने वाली है और मौजूदा व्यवस्था का विघटन होने वाला है। इस विघटन को जो बेहतर ढंग से साध लेगा, राजनीतिक लाभ उसी को मिलेगा।

दोहरे लाभ वाला बड़ा फैसला, सिंधु जल समझौते का स्थगन आतंक के खिलाफ त्वरित कूटनीतिक प्रतिक्रिया

भारत के लिए आवश्यक है कि वह इस संधि स्थगन के आलोक में अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। इसमें पहली प्राथमिकता बरसर और सावलकोट बांध परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन की होनी चाहिए। इसके लिए 2030 तक चार मिलियन एकड़ फीट की भंडारण एवं निस्तारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए जवाबी कदमों में सबसे अधिक चर्चा 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के स्थगन की है। पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष–परोक्ष युद्धों और निरंतर आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने कभी इस समझौते से कदम पीछे खींचने का नहीं सोचा, जिससे उसे शायद ही कोई लाभ मिल पा रहा था। ऐसे में उसे स्थगित करने संबंधी भारत के दांव को महज त्वरित कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, अपितु राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग की रणनीति का नए सिरे से रेखांकन कहना कहीं अधिक उचित होगा। इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, जिससे जम्मू–कश्मीर और

पंजाब में पानी की आपूर्ति–उपलब्धता सुधरेगी। तात्कालिक दौर पर भारत का यह कदम भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन दीर्घकाल में यह सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में बहुत सहायक बनेगा। इस संधि से जुड़ी बाधाओं से मुक्ति के बाद देश को घरेलू फायदे के लिए पानी के उपयोग की गुंजाइश मिल गई है। यह नीतिगत परिवर्तन पश्चिमी नदियों के पानी को पूर्वी नदी प्रवाह तंत्र विशेषकर रावी और ब्यास से जोड़ने की राह खोलेगा, जिनका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खेती के लिए जीवनरेखा जैसा है। यदि सिंधु जल संधि के स्थगन को अपेक्षित रूप से अमल में लाया गया तो यह कदम राज्यों के बीच पानी को लेकर विवादों पर विराम लगाने के साथ ही नहर सिंचित कृषि की कायापलट करने वाला सिद्ध हो सकता है। संधि की स्थगन अवधि तमाम लंबित प्राथमिकताओं की पूर्ति का अवसर बन सकती है। संधि के प्रविधानों के चलते अधर में अटकी पनबिजली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी जाएं। संस्थागत क्षमताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के चलते एनएचपीसी को यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। सिंधु की मुख्य धारा पर भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित करने पर मंथन हो। इससे भारत के दोहरे हितों की पूर्ति होगी। एक तो भारत के विकास संबंधी एजेंडे को गति मिलेगी तो दूसरी ओर भू–राजनीतिक परिवेश में पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी मिलेगा। इस संधि के अंतर्गत अभी तक भारत केवल 5.6 प्रतिशत पानी का ही उपयोग कर पा रहा था। चूंकि अब यह संधि स्थगित हो गई है, इसलिए बरसर बांध जैसी परियोजनाएं गति पकड़ सकती हैं। इसके जरिये 45,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह, चिनाब से दक्षिण कश्मीर के बागानों में सौर ऊर्जा के उपयोग से लिफ्ट इरिगेशन के जरिये 18,000 हेक्टेयर भूमि को उच्च–मूल्य वाली फसलों के क्षेत्र के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। पश्चिमी नदियों के पानी को मोड़ने का असर बहुत दूरगामी होगा। इस साल जून से परिचालन में आने वाली शाहपुर कंडी और प्रस्तावित प्रस्तावित परियोजनाओं के जरिये ही 3.8 से चार मिलियन एकड़ फीट पानी रावी–ब्यास नदी तंत्र में बढ़ेगा। इससे पंजाब में नहर सिंचाई का दायरा 7,80,000 हेक्टेयर से बढ़कर 11 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। राजस्थान के लिए रावी–ब्यास के पानी की पात्रता के 80 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति हो जाएगी। हरियाणा के साथ पानी की साझेदारी के समीकरण सुधरेंगे। इस राह में जोखिम के साथ ही भू–राजनीतिक एवं पारिस्थितिकीय पहलुओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। पाकिस्तान पश्चिमी नदियों पर ही व्यापक रूप से निर्भर है। ऐसी स्थिति में पानी बंद होने से उसकी 1.2 करोड़ एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। खासतौर से पंजाब और सिंध प्रांत मुश्किलों में घिर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चिनाब और झेलम पर विशाल बांध बनाने से तलछट की कमी पंजाब के जलोढ़ मैदानों की उर्वरता पर बुरा असर डाल सकती है।

इससे निपटने के लिए वहां खेती के तौर–तरीके बदलने पड़ सकते हैं। यह सब संभव हुआ तो संधि स्थगित करने का भारत का दांव पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को करारा जवाब और इसका सूचक भी होगा कि उससे निपटने के लिए भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह इस संधि स्थगन के आलोक में अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। इसमें पहली प्राथमिकता बरसर और सावलकोट बांध परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन की होनी चाहिए। इसके लिए 2030 तक चार मिलियन एकड़ फीट की भंडारण एवं निस्तारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया जाए। सीमित अधिकारों के साथ वाटर ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया जाए। रावी–ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल केवल रावी–ब्यास के पानी के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वितरण तक केंद्रित रहे। जबकि चिनाब और झेलम के पानी पर फैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। इसमें पानी के अधिशेष प्रवाह की पात्रता पंजाब और जम्मू–कश्मीर जैसे उसके तटीय राज्यों को दी जानी चाहिए। इस पानी से जल राशियों को रीचार्ज करने की राह भी तलाशी जा सकती है। अधिशेष पानी के कम से कम 15 प्रतिशत का उपयोग दक्षिणी एवं दक्षिणी–पश्चिमी पंजाब में जलराशियों के रीजार्च में किया जाना चाहिए। इससे भूजल में आ रही गिरावट को कम करने, जलस्तर को स्थायित्व देने और किसी भी आशंकित सूखे की स्थिति से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। इस परिवर्तन से जिन परियोजनाओं की संभावनाएं जगी हैं उनसे न केवल जम्मू–कश्मीर और पंजाब में दो लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि तक सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, बल्कि नेशनल ग्रिड को अतिरिक्त 3,000 मेगावाट स्वच्छ पनबिजली मिल सकेगी। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय दर्जे वाली होनी चाहिए, जिसमें शत–प्रतिशत केंद्रीय अंशदान से सिंचाई एवं बिजली जैसे पहलुओं को साधा जाए। यह केवल आर्थिक रूप से अपरिहार्य नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा एवं समतापूर्ण विकास के प्रति राजनीतिक दृढ़ता का भी परिचायक होगा। यह इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से अपूर्णताओं को पूर्ण करने और निर्भरता को संप्रभुता में बदलने का अवसर है।

यह कदम जल सुरक्षा के एक नए युग का सूत्रपात करने के साथ ही पंजाब और जम्मू–कश्मीर में नई कृषि क्रांति की आधारशिला रखने एवं भारतीय राष्ट्र–राज्य के नए हौसले का प्रतीक भी बनकर उभरेगा।

शत्रु न चैन से रहेगा–न रहने देगा, ठंडे दिमाग से पाकिस्तान का शर्तिया इलाज जरूरी

निःसंदेह इतने बड़े देश में सब कुछ आदर्श स्थिति में नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने जो गहन संकट खड़ा किया है उसके कारणों और उससे निपटने के तरीकों को लेकर असहमतियां–विवाद के साथ सरकार की आलोचना–निंदा भी होगी लेकिन आखिर यह समझने में क्या कठिनाई है कि निशाने पर हम सब हैं? भारत के प्रति घृणा में डूबे पाकिस्तान ने पहलगाम में भीषण आतंकी हमला करा कर यही साबित किया कि वह न तो खुद चैन से रहेगा और न हमें रहने देगा। पहलगाम के पहले 2013 में नैरोबी के एक माल और 2016 में ढाका के एक कैफे में जिहादियों ने लोगों से कलमा (मुस्लिम होने की जरूरी निशानी) सुनाने की मांग कर हत्या की थी। क्या आतंक का मजहब होता है? इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन इस पर बहस की गुंजाइश नहीं कि इन हमलों को अंजाम देने वाले मजहबी प्रेरणा से लैस थे। इसीलिए तो कई मुस्लिम नेताओं ने कहा कि पहलगाम हमले ने हमें शर्मिंदा किया, पर कुछ लोग यह साबित करने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगाए हैं कि आतंकियों ने लोगों का मजहब नहीं पूछा। यह आतंकियों को क्लीनचिट देना है। यह काम पश्चिमी मीडिया भी बेशर्मी से कर रहा है। पश्चिम में शायद ही अधिकांश लोग इस सच से अवगत हों कि पहलगाम में लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया।

पश्चिमी मीडिया की जिहादियों का बचाव करने वाली इस करतूत की कीमत एक दिन पूरा पश्चिम चुकाएगा। पहलगाम हमले को सात दिन बीत चुके हैं, लेकिन आतंकियों का पता नहीं। साफ है कि उन्हें किसी ने शरण दे रखी होगी या फिर कोई उन्हें खाना–पानी दे रहा होगा। कोई स्थानीय उनका साथ न देता तो क्या इतना भीषण हमला होता? यदि आतंकी मारे जाएंगे तो मामूली संतुष्टि ही मिलेगी। यदि पकड़े जाएंगे तो पाकिस्तान फिर से बेनकाब होगा, लेकिन उसकी बेशर्मी पर असर नहीं पड़ेगा। आखिर मुंबई हमले में कसाब के पकड़े जाने से भी उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ा।

यदि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की जाती है तो वह कुछ डरेगा, लेकिन फिर वही करेगा, जो उसने मुंबई, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम में किया। वह नए–नए तरीकों से हमले करेगा। जैसे उसने पहलगाम में किया। आम धारणा थी कि आतंकी सेना, पुलिस, कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों और हिंदू तीर्थयात्रियों को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन पर्यटकों को नहीं। इस बार उन्होंने पर्यटकों में हिंदू चुन कर मारे। एक मुस्लिम और एक ईसाई भी उनके हाथों मारे गए।

संगीत नाटक अकादमी की पत्रकार वार्ता, प्रदेश भर में 30 दिवसीय कार्यशालाओं की घोषणा

रंगमंच सिखाएंगी मनीषा मेहरा

—संवाददाता

बाराबंकी। शुक्रवार को नगर के एक रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संस्कृत विभाग द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोर (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उपाध्यक्ष विभा सिंह (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त), निदेशक शोभित नाहर तथा अभिनेत्री एवं रंग निर्देशिका मनीषा मेहरा भी मंचासीन रहीं। मुख्य अतिथि जयंत खोर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

प्रदेश के 75 जिलों में नाटक, शास्त्रीय संगीत व अभिनय के क्षेत्र में होनहार बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए 30 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं की शुरुआत बाराबंकी के सुगम संगीत प्रभाग से की जाएगी। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष विभा सिंह ने बताया कि वे स्वयं भी अभिनय व गायन के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं और बाल सुधार गृह के बच्चों को भी इन कार्यशालाओं से जोड़कर उनके मानसिक विकास में सहायता दी जाएगी। अकादमी के निदेशक शोभित नाहर ने बताया कि अब तक 1200 से अधिक कलाकारों को शास्त्रीय संगीत से जोड़ा जा चुका है, जिनमें 90 प्रतिशत कलाकार उत्तर प्रदेश से हैं। इस विशेष कार्यशाला का संचालन व प्रशिक्षण मनीषा मेहरा द्वारा किया जाएगा। सुगम संगीत प्रभाग के प्रभात दीक्षित ने इसे अपने संस्थान के लिए सौभाग्य की बात बताया। वहीं बॉलीवुड अभिनेता व रंगकर्मी शरद राज सिंह ने कहा कि बाराबंकी में हो रही फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय कलाकारों को अवसर और रोजगार मिल रहा है। पत्रकार वार्ता का संचालन अभिनेता व सभासद प्रतिनिधि देवेंद्र प्रताप सिंह श्ज्ञानूश ने किया। उन्होंने अकादमी अध्यक्ष से मांग की कि बाराबंकी में नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए नगर पालिका परिषद भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है। अकादमी अध्यक्ष जयंत खोर ने इस प्रस्ताव पर विचार करने और सांस्कृतिक मंत्री से वार्ता करने की बात कही। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित पत्रकारों का आभार भी प्रकट किया।

बिना फिटेनस, परमिट मिलने पर 5 अनाधि त डग्गामार व 4 ओवरलोड सीज

—संवाददाता

बाराबंकी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 15 से 17 मई तक अनाधिकृत डग्गामार वाहनो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत जनपद की प्रवर्तन टीम द्वारा लखनऊ–बाराबंकी समेत विभिन्न मार्गो पर अभियान चलाया गया। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासनध्प्रवर्तन अंकिता शुक्ला एंव यात्रीध्मालकर अधिकारी रवि चन्द्र त्यागी की संयुक्त टीम ने निजी वाहन का कमर्शियल प्रयोग मिलने एंव बिना फिटनेस परमिट शर्तो का उल्लंघन मिलने पर पर 5 डग्गामार वाहनो को जब्त करते हुये थाना मोहम्मदपुर चौकी पर सीज किया। इसके अतिरिक्त 4 ओवरलोड़ वाहनो को भी बंद किया गया।

जिला सैनिक बन्धु की बैठक सम्पन्न, पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान शुरू

—संवाददाता

बाराबंकी। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय की ओर से 16 मई, 2025 को कलेक्ट्रेट लोक सभागार में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अध्यक्षता में जिला सैनिक बन्धु की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश की गई। बैठक में स्टेशन हेडक्वाटर बाराबंकी से 201 सीडीईयू के प्रतिनिधि सूबेदार दिनेश कुमार और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के प्रार्थना–पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और अधिकारियों को संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान सेवा से जुड़े मुद्दों जैसे पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों की सेवा के बाद भी उचित सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके।

पत्रकारों की समस्याओं पर चिंतन के लिए राज्य सम्मेलन बिसवां में 18 मई को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे

—संवाददाता

बिसवां, सीतापुर। पत्रकारों की समस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार– विमर्श तथा चिंतन के लिए बिसवां के स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा केन यूनियन हाल में आगामी 18 मई को राज्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पंजीकृत की जिला इकाई सीतापुर के बैनर तले उक्त कार्यक्रम संपन्न होगा। दो चरणों में होने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो रहा है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलम्ब समिति व एमएलसी पवन सिंह चौहान, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन सिन्हा, राष्ट्रीय महामंत्री बलविंदर सिंह जम्मू, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजेश त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त श्रीवास्तव, प्रांतीय महामंत्री रमेश शंकर पाण्डेय के अलावा जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, समाजसेवी व भारतवर्ष के कई राज्यों से पत्रकार भाग ले रहें हैं। कार्यक्रम आयोजक व वरिष्ठ पत्रकार सिराज अहमद ने बताया कि प्रोग्राम के प्रथम चरण में राज्य सम्मेलन के अंतर्गत आए हुए अतिथियों का स्वागत,सम्मान एवं जिला अध्यक्ष सीतापुर द्वारा पत्रकारों से संबंधित प्रस्ताव के बाद शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह संपन्न होगा। द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश राज्य समिति की कार्यकारिणी का गठन होगा। साथ ही पत्रकार साथियों के अलावा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। आयोजक सिराज अहमद ने कार्यक्रम को सफल बनाने का आवाह्न करते हुए बड़ी संख्या में पत्रकारों से पहुंचने की अपील भी की है।

तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर न करने पर पीटा

—संवाददाता

हैदरगढ़ (बाराबंकी)। तलाक के अभिलेखों पर मनमाने तरीके से हस्ताक्षर करने से मना करने पर पति व अन्य ससुराल वालों ने युवती की पिटाई कर दी। कोतवाली क्षेत्र हैदरगढ़ के गांव मवैया खुर्द के श्रवण कुमार मिश्रा ने बताया दो साल पहले पुत्री चांदनी का विवाह शुभम तिवारी के साथ किया था। विवाह के कुछ समय बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मारते–पीटते थे। परेशान होकर छह माह पहले अपने घर ले आए थे।

पति शुभम तिवारी व ससुर रामकुमार तिवारी ने जबरन दबाव बनाकर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर किया और 15 मई को जबरन हस्ताक्षर करा रहे थे। पुत्री के हस्ताक्षर करने से मना करने पर धारदार हथियार से सिरपर हमला कर दिया जिससे गंभीर चोट आने पर घायल अवस्था में सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराया है। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

आसमान से बरस रही आग, हर कोई बेहाल

—संवाददाता

बाराबंकी। मौसम की मार से हर कोई बेहाल है, गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि आम आदमी से लेकर पशु–पक्षी तक व्याकुल हो उठे हैं। इन दिनों आसमान से आग बरसने लगी है। फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल तेज धूप और गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

शुक्रवार को सुबह से ही धूप के तेवर काफी तल्ख रहे। दोपहर होते–होते सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश में इधर–उधर भटकते दिखे। एसी व कूलर जवाब देने लगे हैं। बिजली की कटौती चरम पर पहुंचने से लोगों की रातों की नींद नदारद हो गई है।

छह घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

—संवाददाता

बाराबंकी। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। जेई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शहर के मोहल्ला पंचशील कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की मरम्मत व बिजली के तारों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसके चलते हजाराबाग व पंचशील कॉलोनी में शनिवार सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुआ किसान

—संवाददाता

कुर्सी (बाराबंकी)। बहरौली में चकबंदी में धांधली का आरोप लगाते हुए किसानों ने शुक्रवार को भी विरोध किया। कब्जा परिवर्तन करने गई चकबंदी टीम के विरोध प्रदर्शन के दौरान बहरौली के किसान उमेश यादव बेहोश हो गए। उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा।

उमेश यादव का कहना है कि उनकी जमीन एक स्थान पर थी जो चकबंदी के दौरान तीन टुकड़ों में बांट दी गई है। आपत्ति करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह राम शंकर, शंकर नाथ, विनोद कुमार व संजय आदि किसानों ने भी चक बनाने में मनमानी व धांधली का आरोप चकबंदी कर्मियों पर लगाया। यह भी बताया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को अभी तक पर्चा 23 नहीं दिया गया फिर भी कब्जा परिवर्तन किया जा रहा है।

इस संबंध में सीओ चकबंदी वीरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि बहरौही पंचायत के किसानों ने पहले चकबंदी कराने से मना किया था लेकिन गांव के ही एक किसान ने हाईकोर्ट में चकबंदी कराने की याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। शिकायतों का भी निस्तारण किया जा रहा है।

नर्सिंग छात्रा का 50 हजार रुपये से भरा बैग ले उड़ा परिचित

—संवाददाता

बाराबंकी। जेल में बंद पिता से मिलने गई नर्सिंग की छात्रा का 50 हजार रुपयों से भरा बैग लेकर उसका परिचित नदारद हो गया। घटना के करीब 23 दिन बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी। बृहस्पतिवार रात पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रामनगर कोतवाली के सलेमपुर मजरे नंदऊपारा गांव निवासी शिवानी ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह शहर के पास स्थित एक कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। 19 अप्रैल को वह अपने भाई के साथ जेल में बंद पिता से मुलाकात करने गई थी।

जेल के बाहर रामनगर के ही बोडामऊ गांव निवासी ननकू खड़े मिले। परिचय होने के कारण ननकू ने शिवानी से कहा कि वह बैग सुरक्षित रखेगा। मुलाकात के बाद वापस ले लेना। शिवानी ने बताया कि वह वापस आई तो ननकू नदारद था। बैग में फीस के 50 हजार रुपये, दो मोबाइल व आधार कार्ड रखे थे।

बताया कि छह मई को ननकू ने धमकी देते हुए रुपये व फोन देने से मना कर दिया। शहर कोतवाल आरके राणा ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है।

ट्रक ने ई–रिक्शा में मारी टक्कर, किशोरी सहित दो की मौत...सात लोग घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे घर

—संवाददाता

बाराबंकी। बाराबंकी में ट्रक ने ई–रिक्शा को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में किशोरी सहित दो की मौत हो गई। जबकि सात लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सभी लोग शादी समारोह से घर लौट रहे थे। यूपी के बाराबंकी में शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे लखनऊ–अयोध्या हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने ई–रिक्शा को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में किशोरी समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के अहमदपुर टोल प्लाजा के आगे मेडवा गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान गुड़िया और रेशमी के रूप में हुई है। घायलों में एक महिला, उसके दो मासूम बच्चे, दो किशोरियां और अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे में घायल 10 वर्षीय सचिन को मामूली चोटें आई हैं। लेकिन, वह हादसे के बाद से काफी डरा हुआ है। उसने बताया कि ट्रक ने सामने से टक्कर मारी थी। सूचना पर सीओ सिटी सुमित त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना।

सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। बताया गया कि सभी लोग सफदरगंज क्षेत्र के उधौली गांव में शादी समारोह में गए थे। देर रात वहां से लौट रहे थे। वह लोग असंदरा थाना क्षेत्र के अपने गांव चंद्रभान पुरवा जा रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया।

पतझड़ के बाद हरा–भरा हुआ पारिजात वृक्ष

—संवाददाता

कोटवाधाम (बाराबंकी)। करीब छह माह के लंबे पतझड़ के बाद एक बार फिर पारिजात वृक्ष हरा–भरा हो गया है। इसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। इसकी सुनहरी छटा भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत दे रही है।सिरौलीगौसपुर तहसील क्षेत्र बरोलिया गांव स्थित महाभारत काल का देव वृक्ष पारिजात का जनवरी में पतझड़ शुरू हुआ था। उसी दौरान इसमें कई प्रकार के रोग लग गए थे। वहीं इसके तने में दीमक भी लगी हुई थी। जिले के वन विभाग के अधिकारियों ने रोग से बचाव के लिए कई प्रकार की दवाओं का छिड़काव और उपाय किया।इससे यह वृक्ष एक बार फिर हरा भरा हो गया है और पूरा प्रांगण इसकी खुशबू से महक रहा है। जनवरी से इस विशालकाय पेड़ में पतझड़ शुरू हो जाता है जो अप्रैल–मई तक चलता रहता है। पारिजात वृक्ष हरा–भरा होने के बाद अपनी सुनहरी छटा से सभी को आकर्षित कर रहा है।यहां स्थानीय जिला छोड़ दूसरे जिले से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। वृक्ष में पत्तियां आ गई हैं, फूल और फल जून अंतिम अथवा जुलाई तक आएगा। यहां के पुजारी मंगलदास ने बताया कि हरे–भरे पेड़ की पत्तियों की खुशबू सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है।अब जुलाई में इस पेड़ में फूल और फल आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद पेड़ की हरियाली दिसंबर तक लगातार बनी रहेगी। सिरौलीगौसपुर वन विभाग के उपनिरीक्षक तुषार कुमार ने बताया कि समय–समय पर दवा का छिड़काव अभी भी किया जा रहा है, वृक्ष किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न होने पाए, इसके लिए वैज्ञानिक सलाह भी ली जाती है।

फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

—संवाददाता

रामनगर (बाराबंकी)। रामनगर क्षेत्र के सीहामऊ गांव निवासी पत्नी पिंकी (25) का शव शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालात में घर के अंदर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

रामनगर इलाके के ही मथुरा गांव निवासी राकेश कुमार शुक्ला ने बेटी पिंकी की शादी 2021 में सीहामऊ निवासी निवासी उमानाथ तिवारी के साथ की थी। सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा था। 14 मई को पिंकी अपने मायके मथुरा गई और 15 मई की शाम ससुराल लौटी थी।

शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पति उमानाथ ने पुलिस से बताया कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ कर अंदर गए तो छत पर लगे हुक में दुपट्टे से बने फंदे से पिंकी का शव लटक रहा था।

हालांकि परिजन उसे लेकर सीएचसी पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिंकी के दो वर्ष का बेटा रुद्रप्रताप व एक माह की बेटी निहारिका है। पुलिस की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार सैयद हैदर ने अपनी मौजूदगी में शव का पंचनामा कराया। सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि हर बिंदु पर पड़ताल की जा रही है।

ट्रैक्टर–ट्रॉली में घुसी बाइक, दो दोस्तों की मौत

—संवाददाता

फतेहपुर/सूरतगंज (बाराबंकी)। मोहम्मदपुरखाला क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे भूसा लादकर खड़ी ट्रैक्टर–ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।मोहम्मदपुरखाला क्षेत्र के ज्योली गांव निवासी राकेश वर्मा का पुत्र रंजीत कुमार (22) व विशेसर गौतम का पुत्र विजेंद्र (19) दोस्त थे। बृहस्पतिवार को दोनों बाइक से कोई सामान खरीदने फतेहपुर कस्बा गए थे। देर शाम दोनों बाइक से घर लौट रहे थे।पुलिस के अनुसार फतेहपुर–मोहम्मदपुरखाला मार्ग पर औरंगाबाद गांव के निकट सड़क किनारे खड़ी भूसा लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली में बाइक पीछे से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पने लगे। सूचना पाकर परिजन पहुंचे और दोनों को सीएचसी फतेहपुर ले गए। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। देर रात विजेंद्र की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। रंजीत को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह रंजीत की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।

नारियल पानी पीने दुकान पर पहुंचे अखिलेश यादव, बागी नेताओं को संदेश देकर भाजपा पर साधा निशाना

संवाददाता

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। जहां उन्होंने सपा के बागियों को संदेश दिया और भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाए। अमेठी जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजनैतिक पारा गरम कर दिया। सड़क किनारे ठेले पर नारियल पानी पीते हुए फेसबुक एकाउंट पर लिखा है कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को बढ़ावा देकर ही ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना पूरा होगा। वहीं भाजपा को घेरते हुए लिखा है कि निवेशकों से भाजपाई एजेंट एडवांस में कमीशन मांग रहे हैं। अधिकारी बदलने के बाद टेंडर भी रद्द किए जा रहे हैं। सपा के बागी विधायक का नाम लिए बिना तंज कसने से भी नहीं चूके। इसी के साथ फल की दुकान पर खरबूजे के वजन का अंदाजा लगाने का उनका वीडियो भी सामने आया है। एक अन्य वीडियो में वह नारियल पानी पीते भी दिख रहे हैं। अखिलेश

यादव ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह व महराजी प्रजापति के बारे में लिखा है कि अमेठी के जिन लोगों ने पाला बदला है वह तीन वजहों से फिर कभी जीत नहीं पाएंगे। एक है एहसान फरामोशी, दूसरी है दगाबाजी, तीसरी वजह है कि वो उस दल में गए हैं, जो खुद के लोगों का सगा नहीं है। दलबदलुओं का क्या होगा। ऐसे लोगों ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर खुद ही फुल स्टाप लगा दिया है। भाजपा चित्रजीवी है। बात यह नहीं होनी चाहिए कि फिर कभी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, बल्कि जनता को यह भरोसा मिलना चाहिए कि फिर कभी हमला नहीं होगा। सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि जहां राम व राष्ट्र का मामला आएगा वह वह हमेशा बागी रहेंगे। रामचरित मानस पर सवाल उठाने वालों के लिए हमेशा बागी रहेंगे। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के लिए हमेशा बागी रहेंगे। 11 थानों में झगड़ा हो और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन नहीं कर पाए अपने ही दायित्वों के निर्वहन के विषय में आदमी को सोचना चाहिए।

पांच की जिंदा जलकर मौत : बस में इमरजेंसी गेट पर थी सुकून से सोने वाली सीट, भाग नहीं सके यात्री

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के किसान पथ पर एक बस में आग लगने से पांच यात्री जिंदा जल गए। मामले की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई। जांच में पाया गया कि बस यात्रियों से ज्यादा तो कमियां ढो रही थी। स्नबादवू छमेरू मोहनलालगंज में किसान पथ पर स्लीपर बस (यूपी 17 एटी 6372) में आग की घटना के बाद आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए उच्चाधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के निर्देश पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) विष्णु कुमार ने बस की तकनीकी जांच की। उन्होंने रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में बस के कागजात तो दुरुस्त मिले, लेकिन तकनीकी स्तर पर बड़ी कमियां सामने आई हैं।

कमियां जो बनीं काल

– बस में अग्निशमन यंत्र के लिए एक भी यंत्र नहीं था। अंदर यात्री छोटे सिलिंडर लेकर यात्रा कर रहे थे जो की बड़ा जोखिम था।

– बस के इमरजेंसी गेट के रास्ते में यात्रियों के लिए सीटें लगा दी गई थीं। इसके चलते आग लगने पर गेट को खोला नहीं जा सका।

– बस के अंदर कपड़े के पर्दे लगाए गए थे। ये पर्दे भी आग फैलने का बड़ा कारण बने जिससे आग तेजी से अंदर फैलती गई।

– खर्च बचाने के लिए बस के इंटीरियर में अग्निरोधी मेटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सस्ते मेटेरियल ने तेजी से आग पकड़ी और बेकाबू हो गई।

– बस के अंदर की गई वायरिंग में भी सस्ते मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया था जो संभवतरू शॉर्ट सर्किट की बड़ी वजह था।

– बस की बॉडी का डाइमेंशन मानकों के अनुरूप नहीं था। अंदर आने–जाने का पैसेज काफी सकरा था जिससे यात्रियों को निकलने में दिक्कत हुई।

– बसों के पहियों में सेंसर नहीं थे जो कि महंगी बसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहियों के तापमान पर ड्राइवर की नजर रहती है।

इन 21 बिंदुओं पर हुई बस की जांच

एसी स्लीपर बस की जांच 21 बिंदुओं पर की गई। इसमें बस की लंबाई, चौड़ाई, प्रवेशद्वार की ऊंचाई व चौड़ाई, खिड़की का आकार, स्लीपर बर्थ की डिजाइन, ऊपरी व निचली बर्थ के बीच की दूरी, हेडरूम, गैंग वे, सीट विन्यास, सर्विस द्वार, अग्निशमन यंत्र, विंड स्क्रीन, इमरजेंसी गेट के बिंदुओं को जांचा गया है।

पूरे थे परमिट, फिटनेस, प्रदूषण के कागज

बस बागपत में ट्रेवेल पॉइंट के नाम से पंजीकृत है। बागपत के सीनियर एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि बस का टैक्स 31 मई 2025 तक जमा है। पिछली बार गोरखपुर से बस की फिटनेस करवाई गई थी, जिसकी वैधता 7 अप्रैल, 2026 तक है। बस का इंश्योरेंस 13 जुलाई तक तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र 22 मार्च 2026 तक वैध है। बस संचालन के लिए स्पेशल परमिट 10 से 16 मई तक के लिए लिया गया था। पिछले दो वर्ष में बस का चालान एक बार भी चालान नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार 46, पुलिस ने बताए 70 यात्री

बस में सवार यात्रियों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवहन विभाग के अफसरों के मुताबिक बस 52 सीटर थी। इसमें करीब 46 यात्री सवार थे। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल का कहना है कि बस में 70 से अधिक यात्री थे।

रास्ते में 16 आरटीओ किसी ने नहीं की जांच

16 आरटीओ पार कर गई एसी स्लीपर बस मोहनलालगंज में आग का गोला बनी बस में पांच मौतें हो गईं। खास बात यह है कि यह बस बिहार से दिल्ली के बीच 1300 किमी का सफर तय कर रही थी। इस रूट पर करीब 16 आरटीओ के क्षेत्र आते हैं। लेकिन बस में इमरजेंसी गेट बंद होने व अन्य खामियों की पड़ताल किसी ने नहीं की। बस के रास्ते में कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद के आरटीओ व एआरटीओ के क्षेत्र आए।

बस अग्निकांड : चीखते रहे बच्चे, जलती रहीं उम्मीदें...राख हो गया पूरा परिवार, लपटों में बच्चों को तलाशती रही मां

किसान पथ पर बस में लगी आग कई परिवारों को लील गई। घटना में पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिसमें से दो मासूम बच्चे भी थे। किसान पथ की वो काली सुबहरू ष्उस सुबह की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी... जब एक चीख, एक हाहाकार ने किसान पथ की खामोशी को चीर दिया। एक आग थी... जो सिर्फ बस को नहीं, कई मासूम जिंदगियों को भी लील गई। पापा... मम्मी... हमें बचा लो... ये मासूम चीखें अब भी गूंजती हैं, उस पिता के कानों में... जिसकी आंखों के सामने उसके नन्हें फूल तड़पते हुए मुरझा गए। एक गर्भवती मां, जलती बस की ओर दौड़ती रही... हर लपट में अपने बच्चों का चेहरा तलाशती रही... एक नन्हा बच्चा... जो अभी श्शमांश्श कहना सीख ही रहा था... अब अनाथ हो चुका है। किसी ने बचपन का दोस्त खोया... किसी ने बेटी, किसी ने मांश। किसान पथ पर मोहनलालगंज में हरिकंशगढ़ी के पास स्लीपर बस में लगी आग में मासूम भाई–बहन, मां–बेटी और युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी निवासी राम बालक गांव से कर्ज लेकर पत्नी व बच्चों के साथ कमाने दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने गांव में एक परिचित से 3500 रुपये कर्ज लिया था। इसमें तीन हजार रुपये बस के परिचालक ने ले लिए थे। राम बालक ने बताया कि सोचा था कि कमाकर बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करुंगा, लेकिन आंखों के सामने दिल के टुकड़े जल गए। अब बस उनकी यादें बची हैं और जीवन का भर दर्द लेकर वापस जा रहे हैं। बेटे देवराज (4) और बेटी साक्षी (2) की मौत के बाद से राम बालक की पत्नी गुड्डी बेसुध हैं। गुड्डी ने बताया कि उनके पति ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुड्डी सात माह की गर्भवती हैं। प्रशासन की मदद से उनके बच्चों का शव बिहार भिजवाया गया।

उधर, पत्नी लख्खी देवी (60) और बेटी सोनी (26) की मौत से अशोक सदमे में हैं। अशोक ने बताया कि वह दिल्ली से पानीपत जाने वाले थे। बेटी के पति ने चार साल पहले आत्महत्या कर ली थी। तब से सोनी उन्हीं के साथ रहती थी। अशोक ने बताया कि उनके दो बेटे प्रयागराज में रहकर मजदूरी करते हैं। प्रशासन की मदद से अशोक पत्नी और बेटी का शव लेकर प्रयागराज रवाना हो गए। दोनों शवों का अंतिम संस्कार प्रयागराज में ही किया जाएगा।

ढाई साल पहले सिर से उठा पिता का साया, अब मां भी छोड़कर चली गई

समस्तीपुर निवासी वृद्ध अशोक महतो के लिए यह हादसा जीवन का सबसे बड़ा सदमा बन गया। उनकी बेटी सोनी (26) और पत्नी लख्खी देवी (60) की भी इस बस हादसे में मौत हो गई। ढाई साल पहले दामाद की आत्महत्या से उबरने की कोशिश कर रहे अशोक अब अपने डेढ़ वर्षीय नाती आदित्य की देखरेख को लेकर चिंतित हैं, जो अब अनाथ हो गया है।

सामने जलते रहे मधुसूदन, पर बचा न पाए साथी

यात्री मधुसूदन (26) अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहे थे। उनके साथी रविकिशन ने बताया कि वह मधुसूदन को लपटों में घिरा देखकर कुछ नहीं कर पाए। समय रहते वे और एक अन्य साथी तो बस से निकल गए, लेकिन मधुसूदन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।

एक नजर में पूरा घटनाक्रम

14 मई

04 बजे शाम : बस यात्रियों को लेकर बिहार के बेगूसराय से दिल्ली के लिए निकली।

11 बजे रात : बस गोरखपुर में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी। 15 मई सुबह

05:00 बजे सुबह : मोहनलालगंज में किसान पथ पर बस पहुंची जहां आग लगी।

05:02 बजे : पुलिस कंट्रोल को आग की सूचना मिली।

05:14 बजे : पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।

06:40 बजे : आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।

06:50 बजे : बस से पांच शव जली अवस्था में निकाले गए।

09:00 बजे : अचानक बस में दोबारा आग लग गई।

09:05 बजे : दमकल की एक गाड़ी फिर मौके पर पहुंची।

09:20 बजे : आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।

बुझने के तीन घंटे बाद दोबारा बस में लगी आग, टैंक व कंप्रेसर फटा

स्लीपर बस में आग लगने पर एसी का कंप्रेसर और डीजल टैंक फट गया। धमाके की गूंज एक किलोमीटर तक सुनाई दी। लपटें दो किमी दूर तक लोगों को दिख रही थीं। सूचना पर दमकल 25 मिनट में 5रू40 तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। पूरी तरह आग बुझाने में एक घंटे लग गए। सुबह करीब नौ बजे एक बार फिर बस में आग लगने की सूचना दमकल को मिली।एफएसओ पीजीआई माम चंद बडगूजर ने बताया कि सूचना पर आनन–आनन फानन दोबारा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एक गाड़ी से 20 मिनट में लपटों पर काबू पा लिया। एफएसओ ने बताया कि पहले आग बुझाने के लिए बस को किनारे किया जा रहा था। आशंका है कि रगड़ के कारण बस के टायर के रिम से चिंगारी निकली और आग लग गई। इस दौरान मौके पर सीएफओ बाराबंकी आरपी राय, एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत मौके पर मौजूद रहे।

शैक्षिक दस्तावेज और जेवर जले, मां–बेटी फूट–फूट कर रोईं

बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही चांदनी और उनकी मां मधु ने बताया कि सारा सामान राख हो गया। चांदनी दिल्ली में नौकरी के लिए अपनी सारी मार्कशीट लेकर जा रही थी। मधु ने बताया कि झोले में जेवर रखे थे। आग से मार्कशीट व जेवर जल गए। इसी तरह कई लोगों का पूरा सामान जलकर राख हो गया। कुछ लोग अपने साथ गेहूं, चावल और अन्य खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे।

मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगने पर रोक, प्रबंध समिति को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं अब 19 को सुनवाई

संवाददाता

लखनऊ। बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगने पर प्रशासन की तरफ से रोक है। फिलहाल प्रबंध समिति को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले की याचिका पर सुनवाई हुई। मेला प्रबंध समिति को फिलहाल हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 मई तय की है। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से कहा गया कि दरगाह पर लगने वाला ज्येष्ठ मेला 18 मई से शुरू होना है। इसलिए, मामले की सुनवाई जल्द की जाए। इस पर कोर्ट ने याचियों की अर्जी मुख्य न्यायमूर्ति को देने की अनुमति दी है। दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से चेयरमैन समेत छह छह लोगों ने याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति ए.आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव–प्रथम की खंडपीठ ने की। इस पर राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका पर अपनी बात रखी। याचियों की ओर से उनके अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्र ने मेला आयोजन की अनुमति देने की दलीलें दीं।

डीएम से मेले की अनुमति देने का आग्रह किया

याचिका में बहराइच डीएम द्वारा 26 अप्रैल को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले की अनुमति नहीं दी गई है। याचियों ने इसे कानून की मंशा के खिलाफ बताया। उन्होंने डीएम से मेले की अनुमति देने का आग्रह किया। इससे पहले आठ मई को सरकारी वकील ने डीएम के आदेश को उचित बताते हुए याचिका का विरोध किया था।

राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया इस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी पर अगली सुनवाई के दौरान गौर करने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार और पक्षकारों को याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब पेश करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले में विपक्षी पक्षकारों का जवाब आने तक अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा। अब राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। इसका प्रतिउत्तर भी याचियों ने पेश कर दिया है।

बिजली बिल की रकम रिफंड कराने का फर्जी मैसेज भेज रहे साइबर ठग, अधिकारी बोले– ऐसे कॉल इग्नोर करें

संवाददाता

लखनऊ। साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं को रकम रिफंड कराने का झांसा देकर ट्रैप कर रहे हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता सावधान रहें और ऐसे कॉल पर भरोसा न करें। बिजली उपभोक्ता एक बार फिर साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिल की रकम को विभाग से वापस करने का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। इन मैसेज में रिफंड करने वाली रकम का भी उल्लेख किया गया है। जो उपभोक्ता इस रकम को पाने के लालच में फंसेगा तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा।

ऐसे फर्जी मैसेज भेजने वालों के बारे में ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा ने बताया कि गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार सहित कई इलाकों के लोगों ने उनसे ऐसी मैसेज भेजे जाने की शिकायत की। रूप कुमार ने उपभोक्ताओं को सुझाव दिया कि वह साइबर ठग के मैसेज के बाद इस सिलसिले में कोई मोबाइल पर कॉल आए तो बात न करें। बात करने से उनके ठगे जाने का अंदेशा रहेगा।

फ्रॉड करने वालों ने बिजली विभाग के नाम पर खोजा नया ढंग

बिजली उपभोक्ताओं को ठगने के लिए साइबर ठग के साथ में विभागीय

लोगों की मिलीभगत भी लग रही है। रूप कुमार का कहना है, ऐसे मेसेज का संज्ञान न लें। कोई भी एप डाउनलोड न करें और न ही पैसा वापस लेने का प्रयास करें वरना खाते से पूरा पैसा निकल सकता है।

उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि नागरिकों को सचेत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सूचना व सभी उपभोक्ताओं को मैसेज के माध्यम से अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त यह भी जांच का विषय है कि फ्रॉड करने वालों को उपभोक्ताओं के खाता संख्या किस प्रकार मिले?

किसी उपभोक्ता को कितने रुपए रिफंड करने का झांसा

खाता संख्या	रकम
5295893903	19014
5664674844	15639
9960527667	30755
5798726950	11211
6583150660	40219

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ के निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को विभाग के द्वारा बिल के संबंध में इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा जाता है।

जिन उपभोक्ताओं को यह मैसेज मिल चुके हैं वह इनको इग्नोर कर दें। मैसेज भेजने वाले कॉल करें तो उनसे कोई बातचीत ना करें नहीं तो ठगे जाएंगे।

मुठभेड़ में डकैती की योजना बना रहे दो हिस्ट्रीशीटर सहित सात शातिर अपराधी गिरफ्तार, दो बदमाश घायल

संवाददाता

लखनऊ। अमेठी में पुलिस मुठभेड़ में डकैती की योजना बना रहे दो हिस्ट्रीशीटर सहित सात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है। मोहनगंज पुलिस व स्वाट और सर्विलांस टीम ने बृहस्पतिवार रात मुठभेड़ के दौरान दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सहित सात अंतरजनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी रस्तामऊ–फूला मार्ग स्थित एक आम के बाग में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस पर जानलेवा फायरिंग के जवाब में की गई कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए, जबकि पांच अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल अभियुक्तों की पहचान मोहनगंज थाना क्षेत्र के गडेहरी गांव निवासी सुनील कुमार दीक्षित और भेलाई खुर्द निवासी अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के रूप में हुई है। इसके साथ ही पकड़े गए अन्य पांचों की पहचान मोहनगंज के रामपुर कोची गांव निवासी अनुज सिंह उर्फ शनि व जमुरवा गांव निवासी मकसूद, इन्हौना के पूरे जोरई मजरे पिपरी अहमदाबाद निवासी आशीष कुमार व कैथा गांव निवासी अजय कुमार और जगदीशपुर के सरेसर गांव निवासी अमन सिंह के रुप हुई। इनके पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस, नकद और डकैती में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए। पूछताछ में सोमवार रात जामो क्षेत्र के जनापुर स्थित देशी शराब की दुकान में 40,000 रुपये की लूट की घटना को स्वीकार किया। बरामद नकदी उसी वारदात की बताई गई है। मौके पर पुलिस हथौड़ा, तारकटर, पिलास, टॉर्च, रस्सी सहित डकैती में प्रयुक्त उपकरण तथा अपाचे और सीडी डीलक्स बाइक बरामद हुई हैं। दोनों बाइकें रविवार रात बरात से चोरी करने की भी बात स्वीकार की है। घायलों को अस्पताल में उपचार करवाने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। 22 मुकदमे सुनील के, 17 धर्मेन्द्र पर दर्ज गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सुनील कुमार दीक्षित के खिलाफ अमेठी व बाराबंकी में हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट समेत 22 मुकदमे, जबकि अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र पर अमेठी, रायबरेली और प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी तिलोई डॉ. अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित करते हुए पैरवी कर सजा दिलाई जाएगी।

कार में बनाया अश्लील वीडियो...विधि छात्र को हनी ट्रैप में फंसाकर मांगे 51 लाख, स्नैपचौट पर हुई दोस्ती

संवाददाता

लखनऊ। युवती के साथियों ने अश्लील वीडियो बनाकर छात्र से 10 हजार रुपये वसूल लिए और फिर 51 लाख रुपये की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्नैपचौट से दोस्ती कर युवती ने एक विधि छात्र को झांसे में लिया। इसके बाद हनी ट्रैप में फंसाकर 10 हजार रुपये वसूले। यही नहीं, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और बदले में 51 लाख रुपये मांगे। परेशान होकर छात्र ने डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव से शिकायत की। इसके बाद चौक थाने में आरोपी युवती सुम्बुल कमाल और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छात्र के चाचा सभासद हैं।

सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग का विज्ञापन दिखाकर पांच निवेशकों से ठगे 3.84 करोड़ रुपये, रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शेयर ट्रेडिंग में फायदा दिखाकर निवेशकों को फंसाया और फिर उनसे 3.84 करोड़ रुपये ठग लिए। साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने पांच लोगों से 3.84 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। जालसाजों ने पहले सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के फर्जी विज्ञापन दिखाए, फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम से झांसे में लिया। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

चौक निवासी विधि छात्र का आरोप है कि दो माह पहले उसके पास स्नैप चौट आईडी पर सुम्बुल कमाल नाम से रिक्वेस्ट आई थी। दोनों में बातचीत होने लगी। सुम्बुल ने बताया कि वह नेशनल कॉलेज में बीकॉम की छात्रा है। 11 फरवरी को छात्र मां के साथ खरीदारी करने निकला था। इस दौरान युवती ने उसे मेसेज किया और कहा कि उसे भी लॉ की पढ़ाई करनी है। युवती ने मिलने के लिए कहा। छात्र मां को बाजार में छोड़ने के बाद युवती से मिलने पहुंचा। युवती पहले से इंतजार कर रही थी। छात्र को देखकर वह कार में बैठ गई। इसके बाद दोनों जेबीपी लॉन की तरफ चले गए।

आरोप है कि पार्किंग में पहुंचने पर युवती ने कपड़े उतार दिए। जबतक छात्र कुछ समझ पाता, उसके पहले ही युवती के कुछ परिचित वहां आ गए और वीडियो बनाने लगे। युवती के साथियों ने छात्र को धमकी दी और 10 हजार रुपये वसूल लिए। इसके बाद युवती के साथ चले गए। घटना के 15 दिन बाद छात्र के पास व्हाट्सएप पर मेसेज आया और 51 लाख रुपये की मांग की गई। मांग पूरी नहीं करने पर आरोपियों ने अश्लील वीडियो छात्र के पिता को भेज दी। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।
सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।